भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 625

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर देने के लिए

सार्क बैठक

625. **प्रो. अच्युतानंद सामंत:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दक्षिण एशिया आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध जैसी चुनौतियों से गुजर रहा है और 2014 के बाद से किसी भी सदस्य देश द्वारा किसी भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार क्षेत्र में संपर्क और व्यापार में सुधार के लिए सार्क के मंच का उपयोग करने के लिए इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) सरकार, दक्षिण एशिया में सभी चुनौतियों से अवगत है, जिनमें से सबसे गंभीर चुनौती सीमा पार से संचालित आतंकवाद की है।

(ग) और (घ) सार्क जिसकी स्थापना संबद्ध एवं एकीकृत दक्षिण एशिया के निर्माण हेतु एक संगठन के रूप में की गई थी, का उद्देश्य इस क्षेत्र में सभी देशों के विकास और उन्नति को बढ़ावा देना है। भारत विविध क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बनाने के लिए विभिन्न पहलों को सहयोग दे रहा है। लेकिन, एक देश द्वारा सीमा-पार से संचालित आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण क्षेत्रीय सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

जहां तक व्यापार का संबंध है, 2006 में लागू हुआ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार, सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है। सेवाओं का कारोबार संबंधी सार्क करार (एसएटीआईएस) नवंबर, 2012 से प्रभावी है।

क्षेत्र में आवागमन-सुविधा को बढ़ाने के लिए, सार्क तंत्र की पहलों में सार्क क्षेत्रीय रेलवे और मोटरवाहन करार शामिल है। इनका प्रस्ताव 2014 में किया गया था, परंतु अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। क्षेत्रीय वायु सेवा करार का एक मसौदा भी विचाराधीन है।

***